Times of India
23-3-2023

Minister hails sustainable utilisation for conservation

Shivani.Azad@timesgroup.com

Dehradun: "Nature will protect those who protect nature," said minister of state for environment, forest and climate change, Ashwini Kumar Choubey. He was addressing policymakers, scientists and experts from different parts of the world who had gathered at the international workshop on 'Enhancing Ecosystem Services by Improving Forest Quality & Productivity and Sustainable Land and Ecosystem Management (SLEM) Knowledge Dissemination', which started in ICFRE, Dehradun on Wednesday for next two days.

"We as a nation never exploited nature. Instead, we worshiped nature and stressed on sustainable utilisation and circular economy for conservation of forests," he said. The workshop was inaugurated in virtual mode by him. He lauded the efforts of ICFRE in conservation of forests, land degradation and ecosystem.

Arun Singh Rawat, director general, ICFRE, said, "Conservation of natural resources, forests, biodiversity and restoration of degraded lands can be attained through Sustainable Land and Ecosystem Management (SLEM). This can be achieved through increased participation of the local community, conserving biodiversity, and maintaining ecosystem services. The concept of ecosystem services has gained global momentum as it holds immense importance for human wellbeing."

The Pioneer
23-3-2023

Nature will protect those who protect nature :Choubey

PNS ■ DEHRADUN

Nature will protect those who protect nature. The Union minister of State for Environment, Forests and Climate Change, Ashwini Kumar Choubey said this after inaugurating an international workshop on enhancing ecosystem services by improving forest quality and productivity and SLEM knowledge dissemination at the Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) here on Wednesday.

Choubey said that the nature will protect those who protect the nature adding that as a nation India never exploited nature but instead worshipped it. He also stressed on sustainable utilisation and circular economy for conservation of forests.

ICFRE director general Arun Singh Rawat said that the conservation of natural resources, forests, biodiversity and restoration of degraded lands can be attained through Sustainable Land and Ecosystem Management (SLEM). This can be achieved through increased participation of local community, conserving biodiversity, and maintaining ecosystem services. The concept of ecosystem services has gained global momentum as they hold immense importance for human well-being. The total value of ecosystem services (TEV) for India is $1.8 trillion/year.

Additional secretary and financial advisor to MoEFCC Pravir Pandey stressed on green finances and said that the funds should be utilised by research and development organisations in synergy so that it benefits the society.

Additional director general of forests (Forestry) BK Singh complemented ICFRE on successfully implementing the ESIP in Chhattisgarh and Madhya Pradesh.

Over 200 delegates from national and international research organisations from Bangladesh, Bhutan, Japan Malaysia, Nepal and Thailand, Universities, SFDs, representatives from World Bank, FAO, GIZ, UNDP, scientists and officers were present during the inaugural session.

Rashtriya Sahara
23-3-2023

प्रकृति का संरक्षण करना सबकी जिम्मेदारी : अश्विनी

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद में अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित

केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने वर्चुअली किया कार्यशाला का उद्घाटन

देश-विदेश के दो सौ से अधिक प्रतिनिधि कर रहे प्रतिभाग, विभिन्न विषयों पर मंथन

देहरादून (एसएनबी)। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है। कहा कि प्रकृति का संरक्षण करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। यह बात उन्होंने बुधवार को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए कही। 'वन गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार के माध्यम से पारितंत्र सेवाओं की संवृद्धि' विषयक कार्यशाला में देश-विदेश के विषय विशेषज्ञ प्रतिभाग कर रहे हैं।

कार्यशाला को संबोधित करते अतिथि।

केंद्रीय मंत्री ने अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि हम लोग ऐसे समय में एकत्रित हो रहे हैं जब भारत आगामी 25 वर्ष के अमृत काल के लिए नए लक्ष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आईसीएफआरई को सतत भूमि एवं पारितंत्र प्रबंधन पर भूमि निम्नीकरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक उपागम विकसित करने और नई प्रौद्योगिकियों के प्रवर्तन के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना करने की जो घोषणा की थी उसके अनुसरण में परिषद ने विश्व बैंक के सहयोग से भारत में स्लेम के तहत संस्थानिक और नीतिगत मुख्यधारा हेतु एक रोडमैप विकसित किया है। यह रोडमैप भारत के भूमि क्षरण तटस्थता, सतत विकास लक्ष्यों और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों पर दिशा-निर्देश और कार्ययोजना उपलब्ध कराएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि कार्यशाला के निष्कर्ष भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे।

इससे पहले परिषद के महानिदेशक अरुण सिंह रावत ने कार्यशाला में शिरकत कर रहे अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कार्यशाला के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक वन प्रवीर पांडे ने भी प्रकृति संरक्षण पर जोर दिया। कहा कि सतत भूमि और पारितंत्र प्रबंधन के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों, वन व जैव विविधता का संरक्षण तथा बंजर भूमि की बहाली प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए स्थानीय लोगों भागीदारी जरूरी है। हरित वित्त पर भी उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी।

अपर महानिदेशक वन वीके सिंह ने ईएसआईपी को छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने पर परिषद की बधाई दी। वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ञ अनुपम जोशी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक सहभागिता पर जोर दिया। परिषद की उपमहानिदेशक कंचन देवी ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

कार्यशाला में मेजबान भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, जापान, मलेशिया, नेपाल, थाइलैंड व विभिन्न राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संगठनों के दो सौ से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

Shah Times
23-3-2023

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद में तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू

पारितंत्र सेवाओं की अवधारणाएं मानव कल्याण के लिए रखती हैं महत्व : रावत

शाह टाइम्स संवाददाता

देहरादून । भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा 22 से 24 मार्च, तक देहरादून में ध्वन गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार के माध्यम से पारितंत्र सेवाओं की संवृद्धि और एसएलईएम ज्ञान का प्रसार६ पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया जा रहा है। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि अश्विनी कुमार चौबे, केंद्रीय राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार द्वारा बुधवार को ऑनलाइन माध्यम से किया गया।

उद्घाटन सत्र में मंचासीन गणमान्य व्यक्तियों में अरुण सिंह रावत, महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प., बी के सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक वन (वानिकी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, प्रवीर पांडे, अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार; अनुपम जोशी, वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ञ, विश्व बैंक एवं श्रीमती कंचन देवी, उपमहानिदेशक, (शिक्षा), निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) थे।

■ केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन ने किया वर्चुअली उद्घाटन

उद्घाटन सत्र के दौरान अपने संबोधन में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि हम लोग ऐसे समय में एकत्रित हो रहे हैं जब भारत आगामी 25 वर्ष के "अमृत काल" के लिए नए लक्ष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा भा.वा.अ.शि.प. को सतत भूमि एवं पारितंत्र प्रबंधन (एसएलईएम) पर भूमि निम्नीकरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक ठपागम विकसित करने और नई प्रौद्योगिकियों के प्रवर्तन के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना करने की जो घोषणा की थी उसके अनुसरण में भा.वा.अ.शि.प. ने विश्व बैंक के सहयोग से भारत में स्लेम के तहत संस्थानिक और नीतिगत मुख्यधारा के लिए एक रोडमैप विकसित किया है। यह रोडमैप भारत के भूमि क्षरण तटस्थता (एलडीएन), सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) तथा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों पर दिशानिर्देश और कार्ययोजना उपलब्ध कराएगा। महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. ने मुख्य अतिथि, अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कार्यशाला के विषय में प्रारंभिक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सतत भूमि और पारितंत्र प्रबंधन के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों, वनों, जैव विविधता का संरक्षण और बंजर भूमि की बहाली प्राप्त की जा सकती है। यह स्थानीय लोगों की बढ़ती भागीदारी, जैव विविधता के संरक्षण और पारितंत्र सेवाओं को बनाए रखने के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। पारितंत्र सेवाओं की अवधारणाएं मानव कल्याण के लिए अत्यधिक महत्व रखती हैं, इसीलिए यह वैश्विक हलचल का केंद्र है। भारत के लिए पारितंत्र सेवाओं का कुल मूल्य +1.8 ट्रिलियन/वर्ष है। तराई आर्क परिदृश्य और जिम कॉर्बेट जैसे क्षेत्रों में पारितंत्र सेवाओं का कुल मूल्य क्रमशः +6 बिलियन और +2,153,174.3 है। प्रवीर पांडे, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने संबोधन में हरित वित्त पर जोर देते हुए कहा कि अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को धन का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि समाज को उसका लाभ मिल सके। वी के सिंह, अपर महानिदेशक, वन (वानिकी), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने भा.वा.अ.शि.प. को ईएसआईपी को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि इसे अन्य क्षेत्रों में भी दो. हराया जाना चाहिए।

इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में बांग्लादेश, भूटान, जापान, मलेशिया, नेपाल और थाइलैंड के विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विश्वविद्यालयों, राज्य वन विभागों और विश्व बैंक, विश्व खाद्य संगठन, जीआईजेड, यूएनडीपी के प्रतिनिधियों सहित भा.वा.अ.शि.प. के उपमहानिदेशकों, सहायक महानिद. `शकों, संस्थानों के निदेशकों, वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों सहित 200 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित रहे। कंचन देवी, उपमहानिदेशक (शिक्षा) एवं निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

The Hawk
23-3-2023

Nature Will Protect Those Who Protect the Nature: Ashwini Kumar Choubey

- **Hon'ble Minister of State, Ministry of Environment, Forest and Climate Change**

Dehradun (The Hawk): ICFRE is organizing an International Workshop on "Enhancing Ecosystem Services by Improving Forest Quality & Productivity and SLEM Knowledge Dissemination" from 22 to 24th March, 2023 in hybrid mode at ICFRE, Dehradun. The Workshop was inaugurated by the chief guest Shri Ashwini Kumar Choubey, Hon'ble Minister of State, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), Govt of India on 22.03.2023. The dignitaries present on dais were Shri Arun Singh Rawat, Director General, ICFRE, Sh. B. K. Singh, Additional Director General of Forest (Forestry), MoEF&CC, Govt. of India, Sh. Pravir Pandey, Additional Secretary & Financial Advisor, MoEF&CC, Govt. of India; Sh. Anupam Joshi, Senior Environment Expert from World Bank and Smt. Kanchan Devi, Director (I.C.), ICFRE.

During the inaugural session, Hon'ble Minister of State told that we are meeting at a time when India is setting new goals for the next 25 years of 'Amrit Kaal'. He appreciated the efforts of ICFRE in developing a road map for Institutional and policy mainstreaming of Sustainable Land and Ecosystem Management (SLEM) in India with the help of World Bank, as a follow up of announcement made by the Hon'ble Prime minister of India to set up a Centre of Excellence on SLEM at ICFRE, Dehradun to address the issues of land degradation. He emphasized that the nature will protect those who protect the nature and told that we as a nation never exploited the nature instead we worshiped the nature and stressed on sustainable utilization and circular economy for conservation of forests. He congratulated ICFRE for organizing the international workshop.

DG, ICFRE welcomed the chief guest and other dignitaries. He told that the conservation of natural resources, forests, biodiversity and restoration of degraded lands can be attained through Sustainable Land and Ecosystem Management (SLEM). This can be achieved through increased participation of local community, conserving biodiversity, and maintaining ecosystem services. The concept of Ecosystem services has gained global momentum as they hold immense importance for human well-being. Total value of ecosystem services (TEV) for India is USD $1.8 trillion/year. Regions like Terai Arc landscape and Jim Corbett have the TEV of 390 billion (US$6 billion) and USD $2,153,174.3, respectively. Sh. Pravir Pandey, Additional Secretary & Financial Advisor to MoEF&CC, Govt. of India stressed on green finances and said that the funds to be utilized by R&D organizations in synergy so that it benefit the society. Sh. B.K. Singh, Additional Director General of Forest (Forestry), MoEF&CC, Govt. of India complemented ICFRE on successfully implementing the ESIP in Chhattisgarh & Madhya Pradesh and further the same to be replicated in other areas. Over 200 delegates from National and international research organizations from Bangladesh, Bhutan, Japan Malaysia, Nepal and Thailand, Universities, SFDs, representatives from World Bank, FAO, GIZ, UNDP, from ICFRE DDGs, ADGs, Directors of Institutes, Scientists & officers were present during the inaugural session. The vote of thanks was delivered by Smt. Kanchan Devi, Director (I.C.), ICFRE.

Uttarakhand Kesari
23-3-2023

प्रकृति का दोहन नहीं, पूजन करना जरूरी : चौबे

केन्द्रीय वन राज्य मंत्री ने किया कार्यशाला का आनलाइन उद्घाटन

देहरादून, 22 मार्च (ब्यूरो) : केन्द्रीय वन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बुधवार को वन गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार के माध्यम से परितंत्र सेवाओं की संवृद्धि और एसएलईएम ज्ञान का प्रसार विषय पर आयोजित कार्यशाला का ऑनलाइन उद्घाटन किया। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद में आयोजित कार्यशाला में उन्होंने कहा कि भारत एक सनातन संस्कृति का देश है जो सर्वथा विज्ञान आधारित है। एक राष्ट्र के रूप में हमने कभी प्रकृति का अविवेकपूर्ण दोहन नहीं किया बल्कि उसकी पूजा की। कार्यशाला 24 मार्च तक चलेगी।

वनिकी संस्थान में आयोजित कार्यशाला में शामिल प्रतिभागी।

वेदों और उपनिषदों को उद्धृत करते हुए केन्द्रीय वन राज्य मंत्री ने कहा कि जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है। उन्होंने वनों के संरक्षण हेतु सतत उपयोजन और चक्रीय आर्थिकी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसे समय में एकत्रित हो रहे हैं जब भारत आगामी 25 वर्ष के अमृत काल के लिए नए लक्ष्य तय कर रहा है। परिषद ने विश्व बैंक के सहयोग से भारत में स्लेम के तहत संस्थानिक और नीतिगत मुख्यधारा हेतु एक रोडमैप विकसित किया है। यह रोडमैप भारत के भूमि क्षरण तटस्थता, सतत विकास लक्ष्यों तथा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों पर दिशानिर्देश और कार्ययोजना उपलब्ध कराएगा।

I- Next
23-3-2023

पर्यावरण के लिए ICFRE कर रही बेहतर काम: चौबे

आईसीएफआरई में वन गुणवत्ता पर तीन दिवसीय इंटरनेशनल वर्कशॉप की शुरुआत

इन देशों के स्पेशलिस्ट ने किया प्रतिभाग

बांग्लादेश भूटान जापान मलेशिया नेपाल थाईलैंड

dehradun@inext.co.in

DEHRADUN (22 March): भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) में वन गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार विषय पर तीन दिवसीय इंटरनेशनल वर्कशॉप शुरू हो गई है. अगले तीन दिन देश-विदेश के विज्ञानी पारितंत्र सेवाओं में वृद्धि और वानिकी में ज्ञान के प्रसार पर अपने विचार रखेंगे. वेडनसडे को वर्कशॉप का इनॉग्रेशन केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अश्वनी कुमार चौबे ने वर्चुअल माध्यम से किया.

ऑनलाइन संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है. प्रकृति की रक्षा की दिशा में आईसीएफआरई अच्छा काम कर रही है. सतत भूमि एवं पारितंत्र प्रबंधन पर भूमि निम्नीकरण के मुद्दों पर साइंटिस्ट कार्यों के लिए पीएम नरेन्द्र मोदी ने उत्कृष्ट केंद्र के रूप में परिषद के दायित्वों की धोषणा की है. इसके अनुरूप परिषद ने रोडमैप भी तैयार कर लिया है. यह अच्छी बात है और भविष्य में इसके बेहतर परिणाम सामने होंगे. इस दौरान अपर महानिदेशक वन वीके सिंह ने भी अपने विचार रखे.

1.8 ट्रिलियन डालर मूल्य

आईसीएफआरई के डायरेक्टर जनरल एएस रावत ने कहा कि सतत भूमि और पारितंत्र प्रबंधन के जरिए जैव विविधता संरक्षण व बंजर भूमि को आबाद किया जा सकता है. कहा, भारत की पारितंत्र सेवाओं का मूल्य 1.8 ट्रिलियन डॉलर है. जिम कार्बेट जैसे क्षेत्रों में ही पारितंत्र सेवाओं का कुल मूल्य 21 लाख डॉलर है. वहीं, केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्रालय के अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार प्रवीर पांडे ने हरित वित्त पर जोर दिया. कहा, अनुसंधान संस्थानों को अपने बजट का यूज इस तरह करना चाहिए, जिससे लोगों को उसका सीधा लाभ मिल सके.

Amar Ujala
23-3-2023

देहरादून में बुधवार को आयोजित कार्यशाला में बोलते वक्ता। - अमर उजाला

जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है : अश्विनी चौबे

देहरादून। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि भारत एक सनातन संस्कृति का देश है, जो सर्वथा विज्ञान पर आधारित मूल्यों के साथ आगे बढ़ता है। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का जिक्र करते हुए कहा कि जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है।

'वन गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार के माध्यम से पारितंत्र सेवाओं की संवृद्धि' विषय पर आयोजित कार्यशाला में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) को सतत भूमि एवं पारितंत्र प्रबंधन (एसएलईएम) के तहत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसके माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों, वनों, जैव विविधता का संरक्षण और बंजर भूमि की बहाली की जा सकती है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में हमने कभी प्रकृति का अविवेकपूर्ण दोहन नहीं किया, बल्कि उसकी पूजा की है।

आईसीएफआरई के महानिदेशक अरुण सिंह रावत ने कहा कि पारितंत्र सेवाओं की अवधारणाएं मानव कल्याण के लिए अत्यधिक महत्व रखती हैं, इसीलिए यह आज वैश्विक हलचल का केंद्र है। केंद्र के अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार प्रवीर पांडे ने कहा कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने संबोधन में हरित वित्त पर जोर देते हुए कहा कि अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को धन का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए, जिससे कि समाज को उसका लाभ मिल सके।

इस अवसर पर वन (वानिकी), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अपर महानिदेशक वीके सिंह, उपमहानिदेशक (शिक्षा) एवं निदेशक कंचन देवी, बीके सिंह, अनुपम जोशी मौजूद रहे। ब्यूरो

200 से अधिक प्रतिनिधि ले रहे भाग

तीन दिन तक चलने वाली कार्यशाला में बांग्लादेश, भूटान, जापान, मलेशिया, नेपाल और थाइलैंड के विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों, विश्वविद्यालयों, राज्य वन विभागों और विश्व बैंक, विश्व खाद्य संगठन, जीआईजेड, यूएनडीपी के प्रतिनिधियों सहित करीब 200 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।

Buland siyasat
23-3-2023

जो प्रकृति की रक्षा करते हैंप्र ति उनकी रक्षा करती: अश्विनी कुमार चौब

देहरादून। भारतीय वानिकी अनुसंध ान एवं शिक्षा परिषद (भा.वा.अ. शि.प.) द्वारा 22 से 24 मार्च तक भा.वा.अ.शि.प., देहरादून में वन गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार के माध्यम से पारितंत्र सेवाओं की संवृद्धि और एसएलईएम ज्ञान का प्रसार पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया जा रहा है। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि अश्विनी कुमार चौबे राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार द्वारा अश्वनलाइन माध्यम से किया गया। उद्घाटन सत्र में मंचासीन गणमान्य व्यक्तियों में अरुण सिंह रावत, महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प., बी के सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक वन (वानिकी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, प्रवीर पांडे, अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकारय अनुपम जोशी, वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ञ, विश्व बैंक एवं कंचन देवी, उपमहानिदेशक, (शिक्षा), निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) थे। उद्घाटन सत्र के दौरान अपने संबोधन में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि हम लोग ऐसे समय में एकत्रित हो रहे हैं जब भारत आगामी 25 वर्ष के "अमृत काल" के लिए नए लक्ष्य तय कर रहा है। उन्होने कहा कि मुझे हर्ष हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भा.वा.अ.शि.प. को सतत भूमि एवं पारितंत्र प्रबंधन (एसएलईएम) पर भूमि निम्नीकरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक उपागम विकसित करने और नई प्रौद्योगिकियों के प्रवर्तन हेतु उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना करने की जो घोषणा की थी उसके अनुसरण में भा.वा.अ.शि.प. ने विश्व बैंक के सहयोग से भारत में स्लेम के तहत संस्थानिक और नीतिगत मुख्यधारा हेतु एक रोडमैप विकसित किया है। यह रोडमैप भारत के भूमि क्षरण तटस्थता द्धएलडीएनद्ध, सतत विकास लक्ष्यों द्धएसडीजीद्ध तथा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों पर दिशानिर्देश और कार्ययोजना उपलब्ध कराएगा। महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. ने मुख्य अतिथि, अन्य गण्यमान अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कार्यशाला के विषय में प्रारंभिक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सतत भूमि और पारितंत्र प्रबंधन के माध्यम से प्रा तिक संसाधनों, वनों, जैव विविधता का संरक्षण और बंजर भूमि की बहाली प्राप्त की जा सकती है। यह स्थानीय लोगों की बढ़ती भागीदारी, जैव विविधता के संरक्षण और पारितंत्र सेवाओं को बनाए रखने के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। पारितंत्र सेवाओं की अवधारणाएं मानव कल्याण के लिए अत्यधिक महत्व रखती हैं, इसीलिए यह वैश्विक हलचल का केंद्र है। भारत के लिए पारितंत्र सेवाओं का कुल मूल्य द्धजम्टद्ध +1.8 ट्रिलियन वर्ष है। तराई आर्क परिद्रश्य और जिम कॉर्बेट जैसे क्षेत्रों में पारितंत्र सेवाओं का कुल मूल्य क्रमश: +6 बिलियन और +2,153,174.3 है।माननीय मंत्री जी ने कहा कि भारत एक सनातन संस् ति का देश है जो सर्वथा विज्ञान आधारित है। उन्होंने वेदों और उपनिषदों को उद्धृत करते हुए कहा कि जो प्र ति की रक्षा करते हैं, प्र ति उनकी रक्षा करती है। उन्होंने आगे कहा कि एक राष्ट्र के रूप में हमने कभी प्र ति का अविवेकपूर्ण दोहन नहीं किया बल्कि उसकी पूजा की। उन्होंने वनों के संरक्षण हेतु सतत उपयोजन और चक्रीय आर्थिकी पर जोर दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करने के लिए भा.वा.अ.शि.प. को बधाई दी। प्रवीर पांडे, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने संबोधन में हरित वित्त पर जोर देते हुए कहा कि अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को धन का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि समाज को उसका लाभ मिल सके। वी के सिंह, अपर महानिदेशक, वन द्धवानिकीद्ध, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने भा.वा. अ.शि.प. को ईएसआईपी को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि इसे अन्य क्षेत्रों में भी दोहराया जाना चाहिए। इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में बांग्लादेश, भूटान, जापान, मलेशिया, नेपाल और थाइलैंड के विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विश्वविद्यालयों, राज्य वन विभागों और विश्व बैंक, विश्व खाद्य संगठन, जीआईजेड, यूएनडीपी के प्रतिनिधियों सहित भा.वा.अ.शि. प. के उपमहानिदेशकों, सहायक महानिदेशकों, संस्थानों के निदेशकों, वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों सहित 200 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित रहे। कंचन देवी, उपमहानिदेशक (शिक्षा) एवं निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

Dainik Jagran
23-3-2023

जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है

आइसीएफआरई में वन गुणवत्ता पर कार्यशाला का केंद्रीय राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने किया उद्घाटन

जागरण संवाददाता, देहरादून: भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आइसीएफआरई) में वन गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार विषय पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हो गई है। अगले तीन दिन देश-विदेश के विज्ञानी पारितंत्र सेवाओं में वृद्धि और वानिकी में ज्ञान के प्रसार पर अपने विचार रखेंगे।

बुधवार को कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अश्वनी कुमार चौबे ने वर्चुअल माध्यम से किया। कार्यक्रम को आनलाइन संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने कहा कि जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है। सतत भूमि एवं पारितंत्र प्रबंधन पर भूमि निम्नीकरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्कृष्ट केंद्र के रूप में परिषद के दायित्वों की घोषणा की है। इसके अनुरूप परिषद ने रोडमैप भी तैयार कर लिया है। इस अवसर पर अपर महानिदेशक वन वीके सिंह ने भी विचार रखे। कार्यक्रम में बांग्लादेश, भूटान, जापान, मलेशिया, नेपाल व थाईलैंड के विशेषज्ञों समेत विभिन्न राज्यों के वनाधिकारियों ने भी प्रतिभाग किया।

भारत की पारितंत्र सेवाओं का मूल्य 1.8 ट्रिलियन डालर : आइसीएफआरई के महानिदेशक एएस रावत ने सतत भूमि व पारितंत्र प्रबंधन के जरिये जैवविविधता संरक्षण व बंजर भूमि को आबाद किया जा सकता है। भारत की पारितंत्र सेवाओं का मूल्य 1.8 ट्रिलियन डालर है। तराई अर्क परिदृश्य व जिम कार्बेट जैसे क्षेत्रों में पारितंत्र सेवाओं का मूल्य क्रमशः छह बिलियन व 21 लाख डालर है।

हरित वित्त को जरूरत : केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्रालय के अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार प्रवीर पांडे ने कहा कि अनुसंधान संस्थानों को अपने बजट का उपयोग इस तरह करना चाहिए, जिससे आमजन को सीधा लाभ मिल सके।

एफआरआइ स्थित आइसीएफआरई सभागार में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते आइसीएफआरई के निदेशक अरुण सिंह रावत ● जागरण

Garhwal Post
23-3-2023

Nature will protect those who protect it: Minister Ashwini Kumar Choubey

By OUR STAFF REPORTER

DEHRADUN, 22 Mar: ICFRE is organising an International Workshop on "Enhancing Ecosystem Services by Improving Forest Quality & Productivity and SLEM Knowledge Dissemination" from 22 to 24 March in hybrid mode at ICFRE, Dehradun.

The Workshop was inaugurated by the Chief Guest, Ashwini Kumar Choubey, Minister of State, Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), today. Those present on the dais were Arun Singh Rawat, Director General, ICFRE, BK Singh, Additional Director General of Forest (Forestry), Government of India; Pravir Pandey, Additional Secretary & Financial Advisor, MoEF&CC; Anupam Joshi, Senior Environment Expert from World Bank and Kanchan Devi, Director (IC), ICFRE.

In the inaugural session, Minister Choubey said that India is setting new goals for the next 25 years of 'Amrit Kaal'. He appreciated the efforts of ICFRE in developing a road map for institutional and policy mainstreaming of Sustainable Land and Ecosystem Management (SLEM) in India with the help of the World Bank, as a follow up of the announcement made by the Prime Minister to set up a Centre of Excellence on SLEM at ICFRE, Dehradun, to address the issues of land degradation. He emphasised that nature will protect those who protect nature and reminded that, as a nation, India never exploited nature, instead worshiped it. He stressed on sustainable utilisation and circular economy for conservation of forests. He congratulated ICFRE for organising the international workshop.

The DG, ICFRE, welcomed the Chief Guest and other dignitaries. He said that the conservation of natural resources, forests, biodiversity and restoration of degraded lands could be attained through Sustainable Land and Ecosystem Management (SLEM). This can be achieved through increased participation of the local community, conserving biodiversity, and maintaining ecosystem services. The concept of Ecosystem services has gained global momentum as they hold immense importance for human well-being. Total value of ecosystem services (TEV) for India is USD $1.8 trillion/year. Regions like Terai Arc landscape and Jim Corbett have the TEV of 390 billion (US$6 billion) and USD $2,153,174.3, respectively.

Pravir Pandey, Additional Secretary & Financial Advisor to MoEF&CC, stressed on green finances and said that the funds to be utilised by R&D organisations in synergy so that it benefit the society.

BK Singh, Additional Director General of Forest (Forestry), MoEF&CC, complemented ICFRE on successfully implementing the ESIP in Chhattisgarh and Madhya Pradesh and replicate it in other areas.

Over 200 delegates from national and international research organisations from Bangladesh, Bhutan, Japan Malaysia, Nepal and Thailand, Universities, SFDs, representatives from World Bank, FAO, GIZ, UNDP, from ICFRE DDGs, ADGs, Directors of Institutes, Scientists and officers were present during the inaugural session. The vote of thanks was proposed by Kanchan Devi, Director (IC), ICFRE.